मीडिया विज्ञप्ति

भारत में गैर-संचारी रोगों (NCD) का बढ़ता बोझ

सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ताओं ने जंक फूड्स के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेतावनी लेबल और कानून की मांग की

यह देखते हुए कि 4 वयस्कों में से 1 वयस्क मोटापे, मधुमेह या पूर्व-मधुमेह का शिकार है; तेजी से बढ़ रहा बचपन का मोटापा; अस्वास्थ्यकर जंक फूड भारतीय खाद्य संस्कृति की जगह ले रहा है; जो तम्बाकू से भी ज्यादा लोगों की जान ले रहा है, अब प्रभावी विधायी समाधान का समय आ गया है।

नई दिल्ली। 22 सितंबर 2023: *आज जारी एक अग्रणी रिपोर्ट, "द जंक पुश: भारत में अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत- नीति, राजनीति और वास्तविकता", में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, उपभोक्ता समूहों, वकीलों, युवाओं और रोगी समूहों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है की उच्च वसा वाले चीनी या नमक (HFSS) खाद्य पदार्थों या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPF) की बढ़ती खपत की जांच करने के लिए, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जंक फूड कहा जाता है। पहले से पैक किए गए चीनी युक्त पेय पदार्थ, जूस, बेकरी उत्पाद, कुकीज़, चॉकलेट, मिष्ठान्न, स्वास्थ्य पेय, चिप्स, आइसक्रीम और पिज्जा, इसके कुछ उदाहरण हैं। पश्चिम में निराशाजनक बिक्री के डर से, 1990 के दशक के बाद जैसे ही बाजार खुले, अंतरराष्ट्रीय खाद्य निगम भारत में तेजी से उतरे।*

भारत मोटापे और मधुमेह के गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। जैसा कि 2023 ICMR-INDIAB अध्ययन से पता चलता है कि मधुमेह के 10 करोड़ मामले हैं और हर 4 में से 1 व्यक्ति या तो मधुमेह से पीड़ित है या पूर्व-मधुमेह या मोटापे से ग्रस्त है। भारत सरकार ने 2025 तक मोटापा और मधुमेह को बढ़ने से रोकने का लक्ष्य रखा था, जो दूर-दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पोषण ट्रैकर के माध्यम से एकत्र किए गए नए आंकड़ों से पता चला है कि 5 साल से कम उम्र के 43 लाख बच्चे मोटापे या अधिक वजन वाले हैं, जो ट्रैक किए गए कुल बच्चों का 6% है। प्रमुख अंतर्निहित कारकों में से एक बिक्री बढ़ाने के लिए खाद्य उद्योग के व्यापक विज्ञापन और प्रचार तकनीकों के कारण जंक फूड की बढ़ती खपत है।

डब्ल्यूएचओ इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री 2011 और 2021 के बीच 13.37% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ी है। यह स्पष्ट है कि इस बाजार ने भारत में समाज के गरीब वर्गों में प्रवेश कर लिया है।

वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि जंक फूड खाने से व्यक्ति अधिक खाने लगता है, प्रति दिन ~500 अतिरिक्त कैलोरी का उपभोग करता है, और 2 सप्ताह में वजन ~900 ग्राम बढ़ जाता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया कि यूपीएफ की खपत में 10% की वृद्धि से मधुमेह का खतरा 15% तक बढ़ सकता है और हृदय रोगों के कारण समय से पहले मृत्यु दर बढ़ सकती है। UPF की बढ़ती खपत (मतलब 10% से अधिक बनाम दैनिक आहार का 4% से कम) का भारत और दुनिया भर में मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जिसमें हृदय रोग, स्ट्रोक, डिप्रेशन और सभी कारणों से मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है।

भारत सरकार, गैर-संचारी रोगों (NCD) के बोझ से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और सामान्य NCD (2017-22) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना (NMAP) लागू की है। हालाँकि, कमियाँ बनी हुई हैं। जंक फूड की खपत को कम करने के लिए विज्ञापन और लेबलिंग को नियंत्रित करने के ढांचे जैसी इसके सुझावों पर अभी तक कार्रवाई होना बाकी है ताकि जंक फूड की खपत में कटौती की जा सके।

पोषण नीति पर राष्ट्रीय थिंक टैंक NAP*i* के संयोजक डॉ. अरुण गुप्ता ने कहा, "मौजूदा नियामक नीतियां जंक फूड के किसी भी विज्ञापन को कम करने में अप्रभावी हैं, जो ज्यादातर भ्रामक हैं और विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए निर्देशित हैं।" उन्होंने कहा, “भारत में किसी भी कानूनी ढांचे या दिशानिर्देश में प्री-पैकेज्ड जंक या HFSS खाद्य पदार्थों के अधिकांश भ्रामक विज्ञापनों को रोकने, या भ्रामक दावों पर प्रतिबंध लगाने या लोगों को स्वास्थ्य के खतरों के बारे में चेतावनी देने की क्षमता नहीं है। इस इरादे के लिए कि कोई 'भ्रामक विज्ञापन' नहीं होगा, एक स्पष्ट शब्दों में कानून की जरूरत है।'

NAP*i*, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नई अंतर-मंत्रालयी समिति के विकास का स्वागत करता है, जो मौजूदा नीतियों में कमियों को देख रही है। जंक पुश रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ इस आवश्यकता का बिल्कुल जवाब देती है।

रिपोर्ट में 43 जंक फूड विज्ञापनों से सबूत मिलते हैं, जो सिर्फ हिमखंड की नोक है। ये विज्ञापन आमतौर पर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, भावनात्मक अपील, निराधार स्वास्थ्य दावों और लक्षित बच्चों पर

निर्भर थे। किसी भी विज्ञापन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा मांगे गए "सबसे महत्वपूर्ण जानकारी" नहीं दी गई है, एक खाद्य उत्पाद के लिए, उसमें चीनी, नमक या संतृप्त वसा की मात्रा। इसलिए, NAP*i* का मानना है कि ये विज्ञापन भ्रामक हैं।

NAP*i* की सदस्य और सामाजिक वैज्ञानिक नूपुर बिडला कहती हैं, "आप किसी भी विज्ञापित प्री-पैकेज्ड खाद्य उत्पाद को देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि यह HFSS और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड प्रकृति के हैं, जिस में सभी प्रकार के एडिटिव्स, रंग, स्वाद और इमल्सीफायर शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ इंडिया के एक अप्रकाशित अध्ययन के अनुसार, हर महीने केवल 10 चुनिंदा चैनलों पर 200,000 से अधिक ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये विज्ञापन बच्चों को लक्षित करते हैं, माता-पिता की मंजूरी लेते हैं, मशहूर हस्तियों का उपयोग करते हैं, जंक फूड को स्वस्थ रूप में दिखाते हैं। यह ऐसी ही व्यापक और आक्रामक विपणन तकनीकों के कारण है, हम इसे "जंक पुश" कहते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा: "हानिकारक विपणन और विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है जो मोटापे, मधुमेह और मानव स्वास्थ्य और जीवन पर पूरी तरह से टाले जा सकने वाले सरकार के प्रयासों को विफल कर रहा है। और संसद के लिए इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त कानून बनाना पूरी तरह से संभव है, ताकि व्यवसायियों के व्यावसायिक स्वतंत्र भाषण के अधिकार और नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को संतुलित किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह एक तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर और सर्वव्यापी विज्ञापन को देखते हुए जो भारत को दुनिया में सबसे अस्वास्थ्यकर राष्ट्र बना रहा है।

PHFI के प्रतिष्ठित प्रोफेसर डॉ. के श्रीनाथ रेड्डी के अनुसार, “जंक फूड उन पोषक तत्वों का बहुत खराब संतुलन प्रदान करते हैं जिनकी शरीर को वृद्धि, स्वास्थ्य और भलाई के लिए आवश्यकता होती है, जबकि यही हमें उच्च स्तर के नमक, चीनी, अस्वास्थ्यकर वसा और रासायनिक हमें प्रदान करते हैं। जबकि विज्ञान इस बात पर स्पष्ट है कि इन खाद्य पदार्थों को हमारे नियमित आहार से क्यों बाहर रखा जाना चाहिए, व्यावसायिक कारणों से इनकी खपत चिंताजनक स्तर तक बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में इन खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी अपर्याप्त है, जबकि भ्रामक दावे और ऊंचे स्वर वाले विज्ञापन इन उत्पादों की लत को बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य हानि पर तथ्यात्मक जानकारी साझा करके और मजबूत नियामक उपायों के लिए सार्वजनिक मांग पैदा करके इस जंक पुश का मुकाबला करने की आवश्यकता है।

एक अन्य नीति जिस पर नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं गया, वह NMAP का सुझाव है, यानी एक "व्याख्यात्मक" पैकेट लेबल के सामने (FOPL) का अग्रभाग। यह उपभोक्ताओं को खरीदने और खाने का निर्णय लेने से पहले एक चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है। भारत और विश्व स्तर पर उत्पन्न अध्ययन बताते हैं कि "चेतावनी लेबल" अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। जंक फूड के सामने पैकेट लेबल पर FOPL में जैसे उच्च चीनी/नमक या संतृप्त वसा को शामिल करने से खपत कम होने की संभावना है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के कई देश पहले ही दिखा चुके हैं कि ऐसी नीतियां काम कर रही हैं।

भारत के एक प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ और शोधकर्ता प्रोफेसर एचपीएस सचदेव कहते हैं, "फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग (FOPL) पर नीति निर्माण खाद्य उद्योग की भागीदारी से मुक्त नहीं रहा है, जिसके कारण जंक फूड पर "हेल्थ स्टार रेटिंग" की त्रुटिपूर्ण नीति बनी । उन्होंने कहा, “खाद्य उद्योग स्व-नियमन पर जोर दे रहा है, जो 22 देशों के अध्ययन के अनुसार काम नहीं करता है। इसके अलावा, खाद्य और पोषण नीति विकास पूरी तरह से हितों के टकराव से रहित होना चाहिए जैसे कि इज़राइल में है। WHO और UNICEF ने यह भी कहा कि नीतियों को अनिवार्य होने की आवश्यकता है और खाद्य उद्योग को शामिल किए बिना सरकारों द्वारा नीति विकास का नेतृत्व किया जाना चाहिए।

लगभग एक साल हो गया है कि FSSAI, FOPL पर मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए लंबित है।

लोगों को इसे खरीदने से हतोत्साहित करने के लिए जंक फूड की बिक्री पर उच्च GST स्लैब सुनिश्चित करना एक और नीति है जिसका उद्देश्य खपत को कम करना है।

पत्रकारों से बात करते हुए प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट डॉ. वंदना शिवा ने कहा, "गैर-संचारी दीर्घकालिक बीमारी का बोझ मुख्य रूप से जंक फूड / अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से संबंधित है, जो एक महामारी और स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में उभर रहा है। स्वस्थ, विविध भोजन की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य को विनियमित करना सरकार का कर्तव्य है। रिपोर्ट "जंक पुश" समय पर नीतिगत जानकारी प्रदान करती है। औद्योगिक और रासायनिक रूप से उत्पादित खाद्य उत्पाद हमारी खाद्य संस्कृतियों और लोगों के स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी हैं। वे ग्रह को भी नष्ट

करते हैं जबकि पारिस्थितिक पुनर्योजी खाद्य प्रणाली एक स्वस्थ ग्रह और स्वस्थ लोगों में योगदान करती है।

NCD के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की भयावहता को देखते हुए, यह जरूरी है कि भारत को जंक फूड की खपत में वृद्धि को रोकने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य की दिशा में काम करना चाहिए। यह 2025 नहीं तो 2030 या 2035 तक मोटापे और मधुमेह को रोकने के लिए एक तार्किक कदम के रूप में कार्य करेगा। यह रिपोर्ट कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट सुझाव प्रदान करता है।

1. जल्द कारवाही

- जंक फूड के हानिकारक विपणन और खपत के जोखिम को कम करने के लिए, खाद्य कंपनियों या उनके प्रमुख संगठनों या उनके द्वारा समर्थित व्यक्तियों को **नीति विकसित करने के निर्णय लेने का हिस्सा नहीं होना चाहिए।**
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तत्काल, चीनी, नमक और संतृप्त वसा की सीमा स्थापित कर सकते हैं जो सभी जंक फूड और विपणन प्रतिबंधों के लिए व्याख्यात्मक FOPL (चेतावनी लेबल) का मार्गदर्शन करेंगे।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), NMAP में अनुशंसित "**व्याख्यात्मक FOPL"** (चेतावनी लेबल) को लेकर आ सकते हैं।

2. संसद में एक बिल

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण (MoIB) और कानून और न्याय मंत्रालय स्वस्थ भोजन और जंक फूड (UPF, HFSS) को परिभाषित करने और विशेष रूप से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जंक फूड के विपणन और विज्ञापन पर उचित प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से **"भारत में मधुमेह और मोटापे की वृद्धि को रोकने के लिए NCD की रोकथाम" के लिए एक 'बिल' तैयार कर सकते हैं**। उचित प्रतिबंधों में हर माध्यम, स्कूलों में प्रायोजन या छात्रों के लिए उपहार आदि शामिल हो सकते हैं। जंक फूड के टेलीविजन विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

3. मौजूदा विनियमों में संशोधन

- शिशु खाद्य पदार्थों के मामले में, MoIB केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2000 में भी संशोधन कर सकता है; नियम 7 (2) (viii) में उन विज्ञापनों पर प्रतिबंध शामिल है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से HFSS/जंक फूड को बढ़ावा देते हैं।

- उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय CCPA दिशानिर्देश 2022 धारा 8 और 9 में संशोधन पर विचार कर सकता है, जिससे एक अन्य कानून के प्रावधान को हटाकर HFSS खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना स्पष्ट हो जाएगा।

4. विविध कारवाही

- एक अंतर-मंत्रालयी समूह, स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और अन्य सार्वजनिक सेवा कार्यालयों/क्षेत्रों को एचएफएसएस/जंक फूड नहीं परोसने और किसी भी प्रकार के खाद्य उद्योग प्रायोजन में संलग्न नहीं होने का निर्देश देने के लिए दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।
- GST परिषद UPF और अन्य जंक फूड्स के लिए उच्चतम GST स्लैब पर विचार कर सकती है, जो कोला पेय के लिए "सिन" कर के समान है।
- हितों के टकराव के बिना अकादमिक और नागरिक समाज संगठनों का एक व्यापक गठबंधन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार की सहायता कर सकता है ।

#EndTheJunkPush

#WhoIsEatingWhom

समाप्त

संपर्क:

सुश्री नुपुर बिडला nupurbidla@gmail.com 9958163610

सुश्री रीमा दत्ता reema@bpni.org 9354217803

डॉ. अरुण गुप्ता arun.ibfan@gmail.com 9899676306

NAPi के बारे में जानने के लिए http://www.napiindia.in/